बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 03 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 07 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण न देने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण नीति लागू न करने पर केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ब्रेक-थ्रू जजमेंट में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे कि ट्रांसजेंडर्स को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग मानते हुए उन्हें आरक्षण दिया जाए परंतु अब तक सरकारों ने इस पर कोई ठोस नीति नहीं बनाई. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार की याचिका से जुड़ा है जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पद पर भर्ती में आरक्षण की मांग की थी. चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस याचिका को जनहित याचिका में बदलते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण से जुड़ा है.

सनातन का अपमान नहीं सहेंगे कहते हुए वकील ने सीजेआई गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की। यह घटना तब घटी जब सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही थी। सूत्रों के अनुसार, वकील मंच के पास गया और अपना जूता निकालकर जज पर फेंकने की कोशिश की। हालांकि, अदालत में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वकील को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते समय वकील को यह कहते सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा इस सब से विचलित न हों। हम विचलित नहीं हैं। ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं। यह घटना संभवतः खजुराहो में भगवान विष्णु की सात फुट ऊँची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना से संबंधित एक पूर्व मामले में मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणियों से प्रेरित थी। उस मामले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था जाओ और देवता से ही कुछ करने को कहो।

तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो अभी जाकर प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अनुमति वगैरह देनी होगी। इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था और कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया था। दो दिन बाद खुली अदालत में इस विवाद पर बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ... यह सब सोशल मीडिया पर हुआ।+ केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश का समर्थन करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर अक्सर घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

पीएम मोदी इस महीने करेंगे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का उद्घाटन

नई दिल्ली।

देश के लिए यह महीना बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भारत को दो बड़े एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी अक्टूबर महीने में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (जेवर) का उद्घाटन करेंगे। यह दोनों एयरपोर्ट लंदन के हीथ्रो और अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट्स को टक्कर देते नजर आएंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही एयरोड्रोम का लाइसेंस दे दिया है। जेवर एयरपोर्ट को भी जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 1,160 हेक्टेयर में फैला यह एयरपोर्ट 19,647 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस एयरपोर्ट का काम 5 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के तहत यह एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स और 5 लाख टन कार्गो की क्षमता का वहन कर सकता है। वहीं, एयरपोर्ट का काम पूरा होने के बाद यहां 4 टर्मिनल होंगे, जिससे इसकी क्षमता बढ़कर 9 करोड़ पैसेंजर्स और 3.25 मिलियन टन कार्गो की हो जाएगी। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी देश की टॉप एयरलाइन कंपनियों के विमान नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। यह एयरपोर्ट महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट का 74 प्रतिशत हिस्सा है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर)

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हवाई यात्रा काफी आसान हो जाएगी। उद्घाटन के 45 दिन बाद जेवर एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने की संभावना है। पहले चरण के तहत सिर्फ एक रनवे शुरू होगा, जिसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ पैसेंजर्स की होगी। जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर सालाना 7 करोड़ पैसेंजर्स की हो जाएगी। यह एयरपोर्ट 2 बिलियन डॉलर (लगभग 17,756 करोड़ रुपये) की लागत से बनकर तैयार होगा।

टिकट बुकिंग

नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, नोएडा एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है।

दिल्ली में 18 साल की एमबीबीएस छात्रा का रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, शिकायत में कई गंभीर आरोप

नई दिल्ली । दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. 18 साल की एक एमबीबीएस छात्रा ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज करवाई है. युवती बीएसए मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा है. फिलहाल डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही है. युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी अमनप्रीत (20) हरियाणा के जींद का रहने वाला है. उसने अपने साथियों के साथ 9 सितंबर को उसे दोस्ती और मिलने के बहाने बहकाया. आरोप है कि उसे मादक पदार्थ देकर दिल्ली के होटल एप्पल में जबरन बंद कर दिया गया. युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और अश्लील फोटो और वीडियो बनवाए. इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया या किसी को बताया, तो ये फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे. युवती लगातार डर और मानसिक उत्पीड़न का शिकार रही. शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने युवती को कई बार उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया.

धमकियों और डराने-धमकाने के कारण युवती मानसिक रूप से परेशान रही. आरोपी ने इसे लगातार जारी रखा और युवती को मानसिक प्रताड़ना दी.युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर थाने में FIR दर्ज कर ली. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. यह मामला छात्रों और युवा महिलाओं के लिए एक चेतावनी भी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. युवती के हौसले और साहस को देखते हुए पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान करने की भी बात कही.

बच्चे गुफा में थे, आप कहां थे?, सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली व्यक्ति को लगाई फटकार

नई दिल्ली। कर्नाटक के गोकर्ण की गुफा में दो महीनों तक रह रही एक रूसी महिला और उसकी दो बेटियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कथित पिता को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब आपके बच्चे गुफा में रह रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि भारत अब किसी के भी आने और बस जाने की जगह बन गया है। बता दें, 11 जुलाई को निना कुटिना जो रूस की नागरिक है, वो अपनी दो बेटियों के साथ रामतीर्थ पहाड़ियों की एक गुफा में रहती मिली थी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसा, यह परिवार लगभग दो महीने से गुफा में रह रहा था और उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। बाद में रूसी दूतावास ने निना कुटिना और उनकी बेटियों के लिए आपातकालीन यात्रा दस्तावेज जारी किए ताकि वे अपने देश लौट सके। इस बीच, इजरायल के नागरिक डॉर श्लोमो गोल्डस्टीन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि वह दोनों बच्चियों के पिता हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बच्चियों को फिलहाल रूस न भेजा जाए। गोल्डस्टीन ने बताया कि उन्होंने पिछले साल गोवा के पणजी पुलिस स्टेशन में अपने बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गोल्डस्टीन की याचिका खारिज कर दी और केंद्र सरकार को मां और बेटियों को वापसी की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि निना कुटिना खुद रूस लौटना चाहती हैं और गोल्डस्टीन यह स्पष्ट नहीं कर सके कि बच्चे गुफा में क्यों रह रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा, आपका क्या अधिकार है? आप कौन हैं? कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाइए जो साबित करे कि आप पिता हैं? न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका लगती है। अंत में अदालत ने गोल्डस्टीन को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और टिप्पणी की कि यह देश अब किसी के भी आने और रहने की जगह बन गया है।

जल्दी अमीर बनने का लालच पड़ा भारी, दिल्ली में साइबर ठगों का नेटवर्क हुआ बेनकाब

नई दिल्ली।

अगर आप भी सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर शेयर मार्केट में भारी रिटर्न या आईपीओ में इन्वेस्ट कर बनें अमीर जैसी स्कीम्स देखकर आकर्षित होते हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी है. साउथ-वेस्ट जिले की साइबर पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहा था. डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम (40 वर्ष), मुकुल (33 वर्ष), अक्षय (29 वर्ष), हरीकिशन सिंह (38 वर्ष) और मास्टरमाइंड मंगू सिंह (27 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, नौ चेकबुक, तीन रजिस्टर और आठ सिम कार्ड बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता आर. चौधरी ने बताया कि उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां =इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स का लालच दिया गया. शुरुआत में छोटे-छोटे मुनाफे दिखाकर उनका भरोसा जीता गया. लेकिन जब उन्होंने 10 लाख 70 हजार रुपये का बड़ा निवेश किया, तो उनकी निकासी बंद कर दी गई और ठगों ने उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ऑपरेशन विजयपाल तोमर की देखरेख और एसएचओ प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी निगरानी, मनी ट्रेल और डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया. फर्जी सिम और म्यूल खातों के बावजूद, टीम पहले आरोपी विक्रम तक पहुंची, जिसे हरियाणा के जींद से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर बाकी आरोपी मुकुल, अक्षय, हरीकिशन सिंह और मास्टरमाइंड मंगू सिंह अलग-अलग राज्यों से पकड़े गए. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यह गैंग भारत ही नहीं, बल्कि कम्बोडिया में बैठे विदेशी ठगों से भी जुड़ा हुआ था. छापेमारी के दौरान पुलिस को मिले मोबाइल फोन, लैपटॉप और रजिस्टरों में डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए. इनमें म्यूल अकाउंट्स, चैट्स और लेन-देन के रिकॉर्ड शामिल हैं. अब तक पुलिस ने 4.25 करोड़ रुपये की फ्रॉड मनी की ट्रेल पकड़ ली है, जो अलग-अलग बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट्स के ज़रिए घुमाई गई थी.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बबलू मर्डर केस में खुलासा, नंदू गैंग का गुर्गा गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग को बड़ा झटका देते हुए उसके प्रमुख लॉजिस्टिक सप्लायर हरीश सैनी उर्फ हितेश उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी से हरियाणा के झज्जर जिले के बादली इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक सिंगल शॉट पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी को उसके ठिकाने निहाल विहार से पकड़ा. पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर यह सामने आया कि उसने जुलाई 2025 में झज्जर के लदपुर गांव में हुई संदीप उर्फ बक्लू की हत्या के लिए हमलावरों को ठिकाना, गाड़ी और हथियार उपलब्ध कराए थे. यह हत्या कपिल सांगवान गैंग के इशारे पर की गई थी. स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि हरीश अपने घर पर छिपा है, जब पुलिस टीम ने छापा मारा, तो आरोपी ने भागने की कोशिश की और पिस्तौल तानने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया. इस मामले में स्पेशल सेल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी तीन संगीन मामलों जैसे- लूट, अवैध हथियार रखने और महिला उत्पीड़न में शामिल रह चुका है. उसका बड़ा भाई हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है. पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के दौरान आरोपी गलत संगत में पड़ गया और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया. जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात नंदू गैंग के सदस्यों से हुई, जिसके बाद वह उनके लिए काम करने लगा. दिल्ली पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा चौथा विशाल रक्तदान शिविर व निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का राजपूत चौपाल धर्मशाला

नई दिल्ली (हरफूल सिंह) घोंडा, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर व निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच में मोरल हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क में नाक, कान, गला, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी और दांतों की जाँच व अन्य जाँच की गई। साथ ही इस रक्तदान शिविर में पचास यूनिट खून एकत्रित हुआ। इस रक्तदान शिविर व स्वास्थ्य जाँच शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में घोंडा विधानसभा के विधायक, अजय महावार ने कहा कि इस रक्तदान शिविर व स्वास्थ्य जाँच शिविर के लिए अनुज शर्मा जी और उनकी महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को बधाई देता हूँ और इस तरह के रक्तदान शिविर के आयोजन होते रहने चाहिए कि जिससे और भी लोगों की जान

बचाई जा सके।

और विशिष्ठ अतिथि के रूप घोंडा वार्ड की निगम पार्षद,प्रीति गुप्ता ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य जाँच शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए मैं अनुज शर्मा जी और उनकी महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को बधाई देती हूँ। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर व रक्तदान शिविर में महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिव प्रकाश दीक्षित, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सीए उमेश त्यागी और सह कोषाध्यक्ष हेमचन्द जैन भी शामिल हुए और सहयोग कर्ता के रूप में भारत सेवा चेरिटेबल ब्लड सेंटर का सहयोग रहा और राजपूत चौपाल धर्मशाला व राजपूत मोहल्ला का सहयोग रहा।

एक दशक का सबसे बड़ा कारोबार होगा: कैट का दीपावली पर करोड़ों के बिजनेस का अनुमान, चमकेगा आत्मनिर्भर भारत

नई दिल्ली । दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में उत्साह, उमंग और समृद्धि का माहौल है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि इस वर्ष त्योहारी सीजन में देश का व्यापार 4.75 लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व स्तर को छूने जा रहा है जो पिछले एक दशक का सबसे बड़ा कारोबार होगा। यह न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए भी ऐतिहासिक क्षण होगा। रविवार को कैट के राष्ट्रीय महामंत्री व चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं खोली हैं। जीएसटी दरों में कमी और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति ने बाजारों को नई ऊर्जा दी है। यह दीपावली न केवल घरों को बल्कि देश के लाखों व्यापारियों, कारीगरों, निर्माताओं और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के जीवन को रोशन करेगी। इस बार बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की मांग में उछाल देखा जा रहा है। पारंपरिक बाजारों से लेकर आधुनिक मॉल तक हर जगह उपभोक्ताओं का उत्साह चरम पर है। लोग विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती प्रदान कर रहा है। स्वदेशी की भावना से बाजार जगमगा रहे हैं। यह भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक है। सांसद ने कहा कि दीपावली का कारोबार हर वर्ग के उपभोक्ताओं की भागीदारी को दर्शाता है। लाखों परिवार 500 रुपये या उससे कम की खरीदारी कर रहे हैं तो अन्य लोग हजारों और लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इस विविधता ने दीवाली को देश के रिटेल कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बना दिया है। कैट के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष का कुल व्यापार 4.75 लाख करोड़ रुपये होगा।

भाजपा का नया अध्यक्ष अगले साल

त्रिदीब रमण

राजधानी दिल्ली की बोझिल हवाओं से रावण दहन के धुएं की परतें बारिशों में घुल गई है, एक नए चमकदार दिन का आगाज है और ऐसे ही माहौल में भगवा पार्टी अपने कई अहम फैसलों को सिरे चढ़ा रही है। मौका संघ के शताब्दी वर्ष का भी है, सो कहते हैं अब संघ और भाजपा के बीच रिश्तों के कई अनसुलझे छोर भी खुलते चले गए। भाजपा अब संघ की तारीफ कर रही है और संघ भाजपा की तारीफ कर रहा है। संघ ने भाजपा से साफ कह दिया है कि 'वह अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें संघ का कोई दखल नहीं होगा।' संघ से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि भाजपा के सामुख संघ ने बस इतनी सी शर्त रखी है कि 'जब तक भाजपा अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा संगठन से जुड़े अहम निर्णय नहीं ले सकते। इसके लिए उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड पर निर्भर रहना होगा और संसदीय बोर्ड भी एक सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत काम करेगा।' अभी गुजरात को नया प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, समझा जाता है कि इस पर भी भाजपा नेतृत्व ने एक सामूहिक सहमति बनाने की कोशिश की होगी। कहते हैं संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि 'मलमास-खरमास के बाद ही नए साल में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद भाजपा अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करेगी', कहते हैं शीर्ष भाजपा इस आइडिया को संघ नेतृत्व का भी मूक समर्थन हासिल है। जिन भगवा आकांक्षाओं की गोद में पल-बढ़ कर प्रशांत किशोर ने अपनी सियासी आकांक्षाओं को सींचा है आज अचानक से वे उसी पार्टी के प्रति इतने हमलावर कैसे हो गए हैं? वो भी ऐसे वक्त में जब उन पर भाजपा की 'बी टीम' के तौर पर कार्य करने के आरोप लगते रहे हैं। पीके स्वयं भी ऐसा मानते थे कि भाजपा के साथ उनके रिश्ते किंचित मधुर हैं, पर सारा गेम उन पर पलट गया जब केंद्र सरकार ने पीके के साथ-साथ उनकी पत्नी के एनजीओ को भी निशाने पर ले लिया। पीके से जुड़े विश्वस्त सूत्र का दावा है कि कोई दो हफ्ते पहले पीके को इंकम टैक्स विभाग का एक नोटिस सर्व हुआ था, अभी पीके इस आघात से उबर ही नहीं पाए थे कि केंद्र सरकार ने उनकी पत्नी द्वारा संचालित एनजीओ को निशाने पर ले लिया। सूत्रों का दावा है कि न सिर्फ एनजीओ के प्रबंधकों को आयकर विभाग का नोटिस सर्व हुआ, बल्कि संस्था के कार्यालय पर बकायदा रेड डाल दी गई। यही बात पीके को आहत कर गई, उनका कहना है कि 'उनकी राजनीतिक विचारधारा या गतिविधियों से उनकी पत्नी का क्या ताल्लुक? वह तो बिहार भी मुश्किल से तीन-चार बार आई है।' कहते हैं इस सरकारी कार्रवाई के बाद ही पीके ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, उनके 'नो होल्ड बार्ड' के ऐलान को भी इसी संदर्भ से जोड़ कर देखा जा रहा है। काफी उठा-पटक, खींचतान व धींगामुश्ती के बाद आखिरकार हरियाणा कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह राव नरेंद्र सिंह के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। दरअसल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस शर्त पर अपनी अध्यक्षीय कुर्सी छोड़ना चाहते थे कि 'पार्टी उनकी जगह उनकी पसंद के कैप्टन अजय यादव का चुनाव करेगी।' पर सैलजा व रणदीप सुरजेवाला जैसे नेतागण कैप्टन अजय के नाम का विरोध कर रहे थे, वे कह रहे थे कि 'प्रदेश का नेतृत्व किसी यादव के हाथों में देने के बजाए किसी पंजाबी नेता के सुपुर्द करना चाहिए, क्योंकि हुड्डा अध्यक्षीय छोड़ने के बाद विधायक दल के नेता होने वाले थे यानी जाट स्वाभिमान की रक्षा की पहले से तैयारी थी।' सैलजा ने अपनी ओर से जिन दो नेताओं के नाम आगे किए, उसमें से एक इस बार के चुनाव हार चुके थे, दूसरे की कोई खास राजनीतिक वक्त नहीं था, चूंकि राहुल दक्षिणी अमेरिका के दौरे पर निकल चुके थे, सो मामले से निपटने के लिए हुड्डा सीधे सोनिया गांधी से मिलने जा पहुंचे और उनसे कहा कि 'अगर सैलजा जी की मानें तो हम कुरुक्षेत्र व करनाल जैसे इलाकों में क्यों हार गए, जहां पंजाबी वोटरों का दबदबा है। रही बात जाटों की तो उन्होंने हर सीट पर खुलकर हमारा समर्थन किया है, इसीलिए जाट स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेरा सीएलपी लीडर बनना जरूरी है।' अध्यक्ष भले ही आप किसी न्यूट्रल लीडर को बना दीजिए', इसी समझौते के तहत राव नरेंद्र सिंह का नाम निकल कर सामने आया। जब उनके नाम का भी सैलजा और सुरजेवाला ने विरोध किया तो प्रियंका गांधी ने इन दोनों नेताओं को अपने पास तलब कर उनकी क्लास लगा दी, तब कहीं जाकर नरेंद्र सिंह और हुड्डा के लिए मैदान निष्कंटक हो सका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस 25 सितंबर को धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी तथा केशव प्रसाद मौर्य व सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाने की घोषणा हुई। दरअसल, प्रभारी का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा था। सूत्रों की मानें तो भाजपा चाहती थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव प्रभारी का जिम्मा संभालें। योगी को प्रस्ताव दिया गया था कि 'बतौर प्रभारी वे बिहार के मामले में स्वयं स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं साथ ही उन्हें वहां के चुनावी खर्च का जुगाड़ करना पड़ेगा।' भाजपा को उम्मीद थी कि योगी अपने सीधे उद्घोषों से बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण करा पाने में सक्षम होंगे और अगर एक बार यह चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आसपास सिमट आया तो भाजपा गठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, पर योगी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर नकार दिया, कि 'इतने दिन चुनाव में उलझ गए तो यूपी से उनका ध्यान भटक सकता है, यहां प्रशासनिक फैसले लेने में देरी हो सकती है।' इसके बाद भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव किया, उन्हें बिहार भेजा, पर उन्हें पूरी तरह जिम्मेदारी सौंपने का रिस्क नहीं उठा पाए। दक्षिणी अमेरिका रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कोर कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई थी। राहुल ने उस बैठक में खुल कर कहा था- 'हम जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं चाहे वह 'वोट चोरी' के हों या 'अमेरिकी दबाव' के, आप देखना हमारी पार्टी से ही कई लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी के ही एक-तिहाई लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।' दरअसल, राहुल का इशारा मनीष तिवारी व उनकी मंडली की ओर था, पर बोल गए चिदंबरम। इसके अलावा राहुल ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से कहा कि 'जिन 69 लाख लोगों के नाम बिहार में वोटर लिस्ट से कटे हैं जरा पता करिए वे लोग किन जातियों से ताल्लुक रखते हैं। मेरा अनुमान है कि इसमें से अधिकांश दलित या महादलित हैं।' अल्लावरू ने कहा कि 'यह लिस्ट इतनी बड़ी है, समय इतना कम है, जानना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे।' राहुल ने आगे कहा 'यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है कि सेलेक्टिव जातियों के नाम ही वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। हमें बिहार में घूम-घूम कर यह बात लोगों को बतानी होगी।' अल्लावरू अपने काम में शिद्दत से जुट गए हैं। बिहार में एक आशावादी राजनीति की जोत जलाने का दंभ भरने वाले प्रशांत किशोर भी क्या वहां की जातीय राजनीति के दलदल में फंस गए हैं? नहीं तो क्या कारण है कि पीके की जनसुराज पार्टी राय के भोजपुर, शाहाबाद, बक्सर, काराकट जैसे इलाकों में जो पोस्टर-परचम व स्टिकर लगा रहे हैं उसमें पार्टी के सर्वेसर्वा पीके का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में उनके सरनेम के साथ अंकित है-'प्रशांत किशोर पांडेय'! यानी पीके भी बिहार में अपनी पार्टी के लिए जातीय ध्रुवीकरण का शंखनाद कर चुके हैं।

सम्पादकीय...

बरेली की हिंसा और चुन्ना मियां

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 'आई लव मोहम्मद' नारे को लेकर जो कोहराम मचा हुआ वह पूरे भारत की मलिंडा संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) के विरुद्ध ही नहीं बल्कि नैतिक आचार के भी विरुद्ध है। जहां तक बरेली का सम्बन्ध है तो यह शहर एक तरफ जहां इस्लाम के एक फिरके का मुख्यालय है तो दूसरी तरफ स्व. फज्लुर रहमान उर्फ चुन्ना मियां द्वारा बनाये गये लक्ष्मी-नारायण मन्दिर का भी साक्षी है। बरेली के साहूकारा मोहल्ले में बने इस मन्दिर के लिए चुन्ना मियां ने अपनी जमीन दी, बल्कि पचास के दशक में मन्दिर निर्माण के लिए एक लाख एक रुपये की आर्थिक मदद भी की। मन्दिर निर्माण के समय खुद चुन्ना मियां ने इस मन्दिर के लिए कारसेवा भी दी। मन्दिर में चुन्ना मियां की तस्वीर भी लगी हुई है। यह इस बात का सबूत है कि भारत के मुसलमान भी सामाजिक एकता के लिए पूरी तरह संवेदनशील रहे हैं और हिन्दू संस्कृति के प्रति भी उनका आदर भाव रहा है। चुन्ना मियां का जीवन एक सन्त जैसा था जिनके लिए सभी हिन्दू-मुसलमान सच्चे भारतीय थे। 1960 में जब यह मन्दिर चुन्ना मियां बनवा रहे थे तब भारत के पहले राष्ट्रपति स्व. राजेन्द्र प्रसाद ने भी अपनी शुभ कामनाएं चुन्ना मियां को दी थीं। अतः जिस शहर की विरासत इतनी बुलन्द हो उसमें हिन्दू-मुसलमानों के बीच भाईचारे को नजरअन्दाज करना मूर्खता होगी। मगर हम यह भी जानते हैं कि आजादी के बाद भारत में रह रहे मुसलमानों के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ और इस पूरी कौम को मुल्ला-मौलवियों व इस्लामी आलिमों के भरोसे छोड़ दिया गया। इसके चलते यह समाज शेष भारतीयों की प्रगति के साथ कदम से कदम मिला कर नहीं चल सका। इसका प्रमाण पिछली मनमोहन सिंह सरकार द्वारा मुस्लिमों की माली हालत जानने के लिए गठित सच्चर कमेटी की वह रिपोर्ट है जिसमें खुलासा किया गया था कि मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से भी ज्यादा खराब है। बेशक इंसान का पहला धर्म इंसानियत ही होता है जिसके बाद दुनियादारी में पहचान दिलाने वाले दूसरे धर्म आते हैं। मगर एक सप्ताह पहले जुमे दिन शुक्रवार को बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 'आई लव मोहम्मद' की आड़ में जिस प्रकार साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की उससे यही सन्देश गया कि इस्लाम कथित शान्ति के उलट का परिचय देता है जबकि यह पूरी तरह गलत है। इस्लाम धर्म दुनिया का ऐसा धर्म है जिसमें समानतावादी पुट है, क्योंकि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब सल्ले-अल्लाह-अले-वसल्लम फरमा कर गये हैं कि अपने पड़ोसी का हमेशा ध्यान रखो और देखो कि उसके घर में खाना पका है कि नहीं। इसके साथ रमजान के मौके पर रोजा रखने के साथ ही हर मुसलमान को यह हिदायत है कि वह समाज के गरीब तबके के लोगों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए अंशदान या जकात दे। ऐसा धर्म हिंसा की वकालत कभी नहीं कर सकता। इसी वजह से 1922 के करीब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यंग इंडिया व 1941 के करीब हरिजन पत्र में लिखा कि इस्लाम मूलतः शान्ति का धर्म है। मगर दिक्कत यह है कि मुल्ला-मौलवियों व आलिमों ने इसकी आक्रामकता के पुट को उभारा और इस पर कयामत यह हुई कि पिछली सरकारों ने केवल मुसलमानों के धार्मिक तुष्टिकरण को ही अपना कर्तव्य मान लिया। इस पर तुर्रा यह लग गया कि 1947 में केवल मजहब की बुनियाद पर ही मुसलमानों के लिए अलग से पाकिस्तान बनवा कर अंग्रेज सरकार लन्दन चली गई। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 के पहले स्वतन्त्रता युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच घृणा के बीज बहुत गहरे जाकर बो दिये और बीसवीं सदी में 1906 में मुस्लिम लीग बनवा कर और 1908 में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव मंडल घोषित करके भारत की मलिंडा संस्कृति को भीतर से ही लहूलुहान कर डाला। अंग्रेज यहीं नहीं रुके 1919 में उन्होंने सिख नागरिकों लिए भी पृथक चुनाव मंडल बना डाला। स्वतन्त्र भारत की विडम्बना यह रही कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पूरी कौम को ही अनपढ़ बनाये रखने में पूरी शक्ति लगा दी जिससे उनकी सियासी दुकानदारी फलफूल सके। बरेली में जिस तरह विगत शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा ने दंगा भड़काने का प्रयास किया वह गवाही दे रहा है कि मुस्लिम कौम को धर्म के नाम पर बहलाना-फुसलाना कितना आसान हो सकता है। भारत के मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि स्वतन्त्र भारत में वे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से उतने ही लैस होते हैं जितना कि कोई हिन्दू नागरिक। अतः उन्हें भूलकर भी आवेश में आकर किसी मुल्ला या मौलवी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न किसी दूसरे सम्प्रदाय के प्रति वैमनस्य रखना चाहिए। सभी भारतीय हैं और इस वैभवशाली भारतीय धरा पर निवास करते हैं। जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न है तो उन्हें भी संविधान के दायरे में रह कर अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार करना चाहिए और किसी भी सूरत में दूसरे धर्म के अनुयाइयों के प्रति अनादर व अपमान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बीते दशहरे व नवरात्रे के अवसर पूरे भारत में रामलीलाओं का मंचन होता है जिसमें मुस्लिम नागरिक भी पूरी खुशी के साथ कलाकार बन कर भाग लेते हैं। क्योंकि कलाकार सिर्फ रंगकर्मी ही होता है। बरेली में जिस तरह जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की उसके लिए धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। भारत तो वह देश है जिसमें गुरु नानक देव जी महाराज भी हुए और कबीरदास जैसे महान सन्त भी। भारत की विविधता का वर्णन जितनी संवेदनशीलता के साथ नानकवाणी में किया गया है उसका मुकाबला क्या कोई कर सकता है। यह वाणी इस प्रकार है-

कोई बोले राम-राम कोई खुदाये
कोई सेवे गुसईयां, कोई अल्लाये
कारन कर करण करीम, किरपाधार तार रहीम
कोई नावे तीरथ, कोई हज जाये
कोई करे पूजा, कोई सिर नवाये
कोई पढ़े वेद, कोई कतेब
कोई ओढ़े नील, कोई सफेद
कोई कहे तुरक, कोई कहे हिन्दू
कोई बांचे बहिश्त, कोई सुर बिन्दु
कहे नानक जिन हुकुम पछाता प्रभु साहब के तिन भेद पाया।

'मानवता पर कलंक : दो युद्ध'

मैं पोप पॉल छठे की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने 1965 में कहा था, ''अब और युद्ध नहीं, फिर कभी युद्ध नहीं।'' युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते। ये केवल आक्रोश पैदा करते हैं और शत्रुता को गहरा करते हैं। दुनिया के 51 देशों ने 1945 में उच्च उद्देश्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी। सभी देश शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहें, समृद्ध हों और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। यह निष्कर्ष निकला है कि संयुक्त राष्ट्र विफल है। इसके नेतृत्व में, पिछले 80 वर्षों में कई युद्ध हुए हैं। इस समय दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं। रूस-यूक्रेन - यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। सोवियत संघ के सुनहरे दिनों में, यूक्रेन सोवियत संघ का एक गणराज्य था। यूक्रेन नामक क्षेत्र में कई रूसी और रूसी भाषी लोग रहते थे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन एक संप्रभु गणराज्य बन गया। 2014 और 2022 के बीच, रूस ने क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुगांस्क पर जबरन कब्जा कर लिया। यह कब्जा एक नियति प्रतीत होता है। यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस का तर्क यह था कि यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था और नाटो देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने और रूस को घेरने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन एक संप्रभु देश है। चाहे वह नाटो का सदस्य बने या नहीं, उसे अस्तित्व का अधिकार है और दुनिया को उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। यह युद्ध यूक्रेन के अस्तित्व के लिए खतरा है। 10 सितंबर, 2025 तक, यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन ने कम से कम 14,116 नागरिकों के मारे जाने और 36,481 के घायल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यूक्रेन एक तबाह भूमि है। अस्पताल, स्कूल, आवास, उद्योग आदि सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया है। लाखों नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं (5.6 मिलियन) या अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं (3.7 मिलियन)। दोनों पक्षों के सैनिकों की कुल हताहत संख्या 10 लाख से ज्यादा है, जिनमें उत्तर कोरियाई सैनिक भी शामिल हैं। पश्चिमी देशों द्वारा अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाने के बावजूद जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहता, ऐसा लगता है कि यूक्रेन एक हारा हुआ युद्ध लड़ रहा है। अप्रत्याशित राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं लेकिन वह ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन इस युद्ध में नैतिकता और वैधता के मामले में सही पक्ष में है लेकिन एक अस्थिर संयुक्त राज्य अमरीका और एक नपुंसक संयुक्त राष्ट्र के कारण असहाय है। इतिहास यूक्रेन युद्ध को 2 देशों के बीच लड़े गए सबसे निरर्थक, अनैतिक और असमान युद्धों में से एक के रूप में दर्ज करेगा।

इसराईल-हमास - दूसरा युद्ध हमास द्वारा शुरू किया गया था जो एक उग्रवादी समूह है और फिलिस्तीन के एक हिस्से गाजा पर शासन करता है। इस क्षेत्र ने कई युद्ध देखे हैं। इतिहास के बावजूद, 7 अक्तूबर, 2023 को हमास द्वारा इसराईल पर किया गया हमला पूरी तरह से अकारण और अक्षम्य था। इस हमले में 1200 इसराईली (ज्यादातर नागरिक) मारे गए थे। हमास ने 251 इसराइलियों को भी बंधक बना लिया है। कुछ अभी भी हमास की हिरासत में हैं। इसराईल एक कठोर राज्य है। उसने सभी लोगों को बेदखल करने और पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से गाजा पर लगातार बहु-पक्षीय हमला किया है। यह पहले से ही फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से, पश्चिमी तट के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता है। इसराईल द्वि-राज्य सिद्धांत का कट्टर विरोधी है। गाजा में 67,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। लोग भोजन, पानी और दवाओं के बिना मर रहे हैं। जब मैं यह लिख रहा हूं, यह ज्ञात नहीं है कि हमास राष्ट्रपति ट्रम्प की 20-सूत्रीय 'शांति योजना' को स्वीकार करेगा या नहीं जो इसराईल की मांगों का पर्याप्त समर्थन करती प्रतीत होती है। अगर हमास को तबाह फिलिस्तीनियों को तुरंत राहत देनी है तो उसके पास शायद कोई विकल्प नहीं है। 'शांति योजना' को स्वीकार करने का मतलब होगा फिलिस्तीन के भविष्य को बाहरी नियंत्रण में सौंपना और यह स्पष्ट नहीं होगा कि 157 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त फिलिस्तीन कभी एक संप्रभु राज्य बनेगा भी या नहीं। हमें हमास और फिलिस्तीनी जनता के बीच अंतर करना होगा। निरर्थक युद्ध - भारत ने यूक्रेन युद्ध में कुल मिलाकर एक सैद्धांतिक रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिदूत की भूमिका निभाने की कोशिश की है लेकिन उनके पास वह नैतिक अधिकार और दृढ़ता नहीं है जो भारत को 1950 और 1960 के दशक में हासिल थी। इसराईल-हमास युद्ध में भारत बुरी तरह लड़खड़ा गया था। सरकार ने भारत के इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण को तोड़ा कि इसराईल और फिलिस्तीन दोनों को 'द्वि-राष्ट्र' योजना के तहत अस्तित्व में रहने का अधिकार है। हालांकि, हाल ही में, सरकार को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ है और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस लेख का उद्देश्य केवल उन विनाशकारी युद्धों की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं है जो 'मजबूत' दिखने वाले देश कमजोर विरोधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दुनिया को जवाहरलाल नेहरू, डैग हैमरशॉल्ड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नैतिक अधिकार वाले नेताओं की जरूरत है। दुनिया को ऐसे राष्ट्रों की जरूरत है जो एकजुट होकर झगड़ते देशों पर प्रभाव डाल सकें।

सृष्टि के दो वाहक, मनुष्य और पशु

विश्व पशु दिवस के 100 साल पूरे हो गए हैं। 4 अक्तूबर को इसका आयोजन किए जाने की परंपरा एक जर्मन पशु प्रेमी हाइनरिख जिम्मरमन ने की, जिनका विशेष लगाव कुत्तों से था। धीरे-धीरे इसका स्वरूप विश्वव्यापी हो गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिलती गई। दोस्ती बनाम दुश्मनी - जानवरों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की प्रक्रिया अनादि काल से रही है, एक सहयोगी के तौर पर इनकी पहचान है। फिर भी मनुष्य अधिकतर इनकी प्रकृति न समझने के कारण इन्हें अपना शत्रु मानने की गलती कर देते हैं जबकि ये मित्र और पूरक दोनों हैं। लगभग 100 देशों में यह दिवस मनाया जाता है और इनके लिए आवास, भोजन, सुरक्षित स्थान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक अंग्रेज पीजी ग्रांट ने भारत में कुत्तों और बैलों जैसे पशुओं के प्रति व्यवहार को देखकर सन् 1861 में कोलकाता में एस.पी.सी.ए. का गठन किया था। पूरे देश में आज भी इसके कार्यों की सराहना की जाती है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल और मेनका गांधी के प्रयास इस दिशा में सराहनीय हैं। जो देश वन्य जीवों की बहुतायत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इन्हें अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। जंगल सफारी का चलन सभी देशों में है। सामान्य व्यक्ति जब जंगल में जानवरों के बीच जाता है तो एक ओर उसका डर खत्म होता है और दूसरी ओर इनके बारे में उसकी जिज्ञासा शांत होती है तथा इनकी दिनचर्या समझ आती है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ही टूर पर देखे कुछेक दृश्य स्मृति में हैं। वनराज शेर अपनी मस्त अदाओं से सड़क के दोनों ओर रुकी गाड़ियों के बीच से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई अधिपति राजा महाराजा जाता है। उसके बाद वे झाड़ियों से होकर अपने परिवार के साथ मस्ती करते दिखे। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि अगर उनके साथ छेड़छाड़ हुई तो यह निश्चित रूप से घातक होगा। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के जंगलों में एक शेरनी अपने शिकार का पीछा कर रही थी। वहां एक किसान अपने खेतों में था। उसने कुछ ऐसी आवाजें निकालीं कि शेरनी का ध्यान भटका और उसने पहले उस पर हमला किया और उसके बाद शिकार को मारा। उसके बाद हुआ यह कि वह शेरनी नरभक्षी घोषित हुई क्योंकि उसके मुंह इंसान के खून का स्वाद लग चुका था। इसी तरह जंगल में हाथी विचरते हैं। एक बार इसी तरह ट्रैफिक के बीच से एक पूरा हाथी परिवार गुजर रहा था। अनुशासन और परिवार की जिम्मेदारी इनसे सीखी जा सकती है। सबसे बड़ा हाथी सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसके बाद एक-एक करके बाकी सदस्यों ने सड़क पार की। उसके बाद वह गया। वहां इसने देखा कि उसके परिवार का बुजुर्ग हाथी तो उस पार रह गया। इसने इंतजार किया और जब उसने भी सड़क पार कर ली तो वह आगे बढ़ा। पशुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके लिए इतना ही जान लेना काफी है कि हमारा जो ईकोसिस्टम है।

सरकती जाए है रुख़ से नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता

बादल सरोज

विडम्बनाएं भी कभी कभी इतनी विडम्बनामयी दुविधा में फंस जाती हैं कि एक काव्यात्मक त्रासदी का रूप धारण कर लेती हैं। इस 2025 का 2 अक्टूबर ऐसा ही दिन है : इस दिन महात्मा गांधी, जिनके नाम से भारत को दुनिया में जाना और पहचाना जाता है उनकी जयंती है और ठीक उसी दिन दशहरा होने के चलते गांधी के सोच विचार के एकदम विपरीत और उनकी हत्या में आरोपी और इसके चलते प्रतिबंधित होने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 100वीं सालगिरह भी है। पाखण्ड की हद यह है कि अपनी स्थापना की सौवीं सालगिरह पर यह संगठन एक तरफ शस्त्रपूजन करने जा रहा है वहीं जैसी कि खबर है दूसरी तरफ उसके लोग गांधी प्रतिमा पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गांधी की प्रिय रामधुन का जाप भी करने वाले हैं। वैसे इस तरह की कलाबाजियां दिखाने में संघ जन्मना दक्ष है। शताब्दी वर्ष से पहले विचार का खाका तैयार करने के लिए वर्ष 2022 में अहमदाबाद में हुई इसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के समय लगाई गयी आधिकारिक प्रदर्शनी में इसने जिन 200 राष्ट्रभक्तों की तस्वीरें लगाई थीं उनमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे ; उन्हें भी सच्चा राष्ट्रभक्त बताया गया था। होने को तो इस फोटो गैलरी में वे मृणालिनी साराभाई और सैम पित्रोदा भी थे जिनके पीछे आजकल यह गिरोह हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। शताब्दी वर्ष में इस तरह के और भी कई प्रहसन होने जा रहे हैं। नए मुखौटे, नए-नए छद्म आवरणों की धजा सजाई जाने वाली है। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है इन सौ वर्षों में इस 'संगठन' की कारगुजारियों का आकलन भी किया जाएगा। हालांकि इसे संगठन कहना इसके रूप स्वरूप को कम करके आंकना होगा। संगठन वे होते हैं जिनका संविधान होता है, सदस्यता होती है, खाते और अकाउंट होते हैं। एक विधिवत निर्धारित कार्यपद्धति और उसके निर्वाह की सार्वजनिकता होती है, खुलापन और उत्तरदायित्व होता है ; आरएसएस में इनमें से कुछ भी नहीं है। बहरहाल इसके किये धरे के समग्र लेखे जोखे को बाद के लिए छोड़ते हुए फिलहाल उन 'मूल्यों' की कसौटी पर ही एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं जिनके लिए यह स्थापित होने का दावा करता है। इसका दावा है कि संघ का मिशन सहस्राब्दियों पुरानी विरासत के अनुरूप है, जिसमें मानव जाति की एकता, सभी धार्मिक परंपराओं की अंतर्निहित एकता, मानव की मूल दिव्यता, सजीव और निर्जीव, सभी प्रकार की सृष्टि की पूरकता और अंतर्संबंध, तथा आध्यात्मिक अनुभव की प्रधानता में विश्वास शामिल है। यह भी दावा करता है कि संघ सभी नागरिकों और जीवन की सभी गतिविधियों में देशभक्ति के संचार को प्राथमिकता देने में अद्वितीय है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र, मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का पोषण आवश्यक है। इन सद्प्रेरणाओं का सृजन और पोषण देश के समक्ष सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है - जिसे स्वामी विवेकानंद ने संक्षेप में मानव-निर्माण कहा है। मानव जाति की एकता और सभी धार्मिक परम्पराओं की अंतर्निहित एकता में इसका विश्वास कितना है यह भारत की जनता के द्वारा माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के प्रति इसके खुले वैमनस्य और उनके प्रति खुलेआम की जाने वाली हिंसा के रूप में बिना किसी अंतराल के इन दिनों तो लगभग हर रोज, उजागर होता रहता है। यह चर्चों और उनसे जुड़े संस्थानों को फूंकने, मस्जिदों पर चढ़कर भगवा झंडे फहराते हुए उत्पात मचाने, स्कूल कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई उनके परिधानों के आधार पर रोकने, सार्वजनिक सांस्कृतिक समारोहों में दूसरे धर्मों के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित करने और रेलगाड़ियों में सोते हुए यात्रियों को जगाकर उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देने तक पहले ही जा पहुंचा था। इस तिरस्कार और द्वेष से इसने पृथ्वी के इस हिस्से में जन्मे बौद्ध, जैन, सिख, आजिविक और श्रमण धर्मों को भी नहीं बख्शा। इन दिनों इसने अपना दायरा और बढ़ाकर उसकी लपेट में उन पंथों और सम्प्रदायों और धार्मिक धाराओं को भी ले लिया जिन्हें आमतौर से व्यापक हिंदू धर्म परम्परा का हिस्सा माना जाता था। हिन्दू धर्म के आधार पर हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का दावा अब हिन्दू धर्म की बात करना ही बंद कर चुका है ; उस सनातन पर लौट आया है जिसके खिलाफ हुए तीखे संघर्ष ने ही इस देश की धार्मिक और दार्शनिक परम्परा को समृद्ध किया था। कुछ हद तक मानवीय बनाया था। रही सभी नागरिकों और जीवन की सभी गतिविधियों में देशभक्ति के संचार को प्राथमिकता देने की बात तो इस मामले में तो सचमुच संघ का रिकॉर्ड अद्वितीय है। राजनीतिक भौगोलिक रूप से इस भारत देश का निर्माण जिस 90 वर्षों के महान स्वतंत्रता संग्राम से हुआ उसमें 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आरएसएस ने जो भूमिका निबाही है उसे इसके अंधभक्तों को छोड़कर बाकी देश और दुनिया अच्छी तरह जानती है। स्वतन्त्रता संग्राम का विरोध; 15 अगस्त 1947 के दिन काले झंडे फहराना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपशकुनी बताते हुए धिक्कारना, नए भारत के संविधान निर्माण के खिलाफ आन्दोलन करना इतिहास में दर्ज है। आजादी के मात्र साढ़े पांच महीने के भीतर ही देश के सबसे बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या कर राष्ट्र को अस्थिर बनाने की साजिश रचना इनकी देशभक्ति का एक और उदाहरण है। इनके विचार आराध्य सावरकर की इंग्लैंड की महारानी को लिखी चिट्ठियां आज भी माफीनामों के लेखन का आदर्श प्रतिरूप बनी हुई हैं। संघ के संस्थापक डॉ हेडगेवार की देशभक्ति की गाथा 1920 के दशक में, जब संघ के सह-संस्थापक हेडगेवार इसके पहले सरसंघचालक बने तो जिन बालाजी हुद्दार को पहला सरकार्यवाह नियुक्त किया गया था उन्होंने लिखी हुई है। हुद्दार बताते हैं कि जब वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से मुलाकात के लिए समय लेने हेडगेवार के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बहाना बना कर किस तरह नेताजी से मिलने तक से मना कर दिया था। वे लिखते हैं कि सरसंघचालक उस दिन खूब मजे में स्वयंसेवकों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, बीमार नहीं थे - संघ आजादी के आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता था। उन दिनों वह अंग्रेजी सेना तथा पुलिस में भर्ती करने के अभियान में जुटा हुआ था और अंग्रेजी सरकार के फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ा रहा था। देशभक्ति की 'अद्वितीयता' की यह परम्परा आज तक जारी है : पिछले डेढ़ दशक में पाकिस्तान की आईएसआई के लिए, जासूसी करते हुए जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें जितने इनकी राजनैतिक वैचारिक संबद्धता वाले हैं उतने किसी और के नहीं। अभी दो साल पहले खुद प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चलने वाले सुरक्षा संस्थान डीआरडीओ में पकड़ा गया साईंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर तो तीन पीढ़ी से संघ संस्कारित स्वयंसेवक था। रही चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की तो वे जितना चुप रहें उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। आर्थिक भ्रष्टाचार, व्यापम से लेकर धार्मिक मेलों और मंदिरों तक के नाम पर जितने घोटाले इस कुनबे ने किये हैं उनका मुकाबला तो सकल ब्रम्हाण्ड में कोई नहीं कर सकता। ऐसा करते में इनने अपने उन भगवानों को भी नहीं बख्शा जिनके नाम पर सत्ता में पहुंचे। इस देश में सीडी उद्योग तो इन्हीं के कारनामों के आधार पर खड़ा और फलाफूला है ; इस धतकरम में भी इन्होंने अपने कुनबाईयों को प्राथमिकता देना नहीं भूला। राष्ट्र के एकीकरण और उसे मजबूत शक्ति के रूप में विकसित करने का इनका दावा कितना सच्चा है यह इनके राज में हुए मणिपुर और इन दिनों हो रहे लद्दाख से साफ हो जाता है। बात मजबूती की करते रहे और राष्ट्र को भीतर और बाहर दोनों तरह से कमजोर करते रहे। भारतीय अवाम के भीतर उसके समुदायों, सम्प्रदायों, जातियों और रायों, भाषाओं और संस्कृतियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूजे से अलगाव का जो काम पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पिछले 70 साल में कई अरब डॉलर खर्च करके नहीं कर पाया वह बिखराव, विभाजन और विखंडन का काम सत्ता का आश्रय पाने के बाद आरएसएस ने महज एक दशक में कर दिखाया। सेना में भर्ती पर रोक, अग्निवीर जैसी आत्मघाती और अदूरदर्शी योजनाओं और रक्षा उत्पादनों के निजीकरण और राफेल जैसे महाघोटालों से इस देश की सामरिक सामर्थ्य में जो दीमक लगाई है उसकी भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। यही संकीर्ण और दिवालिया विचारधारा है जिसने एक जमाने में विश्व के सवा सौ देशों के नेता रहे भारत को आज दुनिया भर में इस कदर अलग थलग कर दिया है कि एक भी पड़ोसी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बचे हैं। कुल मिलाकर यह कि इनने भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां इनके रहते अब उसे किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। यही हालत इनके राष्ट्रवाद की है अब किसी जमाने में जम्बू द्वीप कहे जाने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक की भौगोलिकता में बंधा राष्ट्र इनका राष्ट्र नहीं है ; अब अडानी ही राष्ट्र है राष्ट्र तो अडानी है। इस कदर कि देश, संविधान, राजनीति यहाँ तक कि धर्म तक की आलोचना की जा सकती है किन्तु उनकी नहीं। हर फासिस्ट, हर तानाशाह, हर आतंकी मूलतः कायर होता है वह अपने से बड़े को अपना बड़ा मानता है। जब जब, जो जो बड़ा होता जाए उसे बड़ा मानता रहता है। सौ साल के हो रहे संघ के साथ भी यही है। इसके संस्थापक लिखापढ़ी में अपने जमाने के सबसे बड़े जालिम हिटलर को अपना आदर्श मानते थे, यहूदियों का सफाया करने के उसके बर्बरतम काम की सराहना करते हुए उससे सीखने की बात करते थे। आज वे यहूदीवादी नरसंहारी बेंजामिन नेतन्याहू के दीवाने बन उसकी आराधना कर रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/08882)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे के दौरान जापान की सेइरेन कंपनी ने हरियाणा के साथ किया एमओयू

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की प्रतिष्ठित सेइरेन कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सेइरेन कंपनी रोहतक में अपने मेगा प्रोजेक्ट में 220 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इस परियोजना से लगभग 1700 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि सेइरेन कंपनी लिमिटेड वस्त्र समाधान और ऊनत सामग्री निर्माण में विश्व स्तर पर अग्रणी कंपनी है, जिसके उत्पाद ऑटोमोबाइल, इंटीरियर, पर्यावरण संरक्षण, लाइफस्टाइल, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेंसर और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कई क्षेत्रों में उपयोग होते हैं।

एक सशक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बनी हरियाणा की पहचान

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, युवा आबादी व बड़ा बाजार तथा जापान के तकनीकी कौशल, विनिर्माण कौशल और वित्तीय संसाधन दोनों देशों की प्रगति में अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की पहचान एक सशक्त औद्योगिक और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बनी है। हरियाणा, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 1.3 प्रतिशत है। लेकिन, यह देश की जी.डी.पी. में 3.6 प्रतिशत का योगदान देता है। हरियाणा हमेशा से भारत में जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल रहा है। हरियाणा भारत के निर्यात में योगदान देने वाला प्रमुख राज्य है। हरियाणा ने वर्ष 2023-24 में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 2,000 से अधिक वस्त्र इकाइयां हैं। हरियाणा भारत के वस्त्र उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो सिंथेटिक और विशेष वस्त्रों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आईटीआई और कई कौशल विकास केंद्र हैं, जो वस्त्र निर्माण और विनिर्माण पर केंद्रित हैं। इससे कुशल मैनपावर भी उपलब्ध होगी। सेइरेन कंपनी के साथ हुए एमओयू से हरियाणा इस क्षेत्र में और अधिक प्रगति होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह निवेश राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को नई गति देगा और हरियाणा को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर और मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से राज्य में औद्योगिक नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन में अब तक 1014.19 करोड़ की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित

चंडीगढ़। हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025 - 26 के दौरान किसानों के खातों में अब तक 1014.19 करोड़ की अदायगी उनके बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जा चुकी है। इस तरह सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीद की जा रही है। राज्य में अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 81410 किसानों से धान की खरीद की गई है। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ जानकारी देते हुए कहा कि अब तक राज्य भर की मंडियों में कुल 13.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न जिलों की मंडियों से अब तक 5.65 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हो चुका है। अब तक मंडियों से 10.00 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है हरियाणा की मंडियों/खरीद केंद्रों में धान की खरीद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में धान की खरीद भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए फसल का भुगतान किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित किया जाता है। सरकार द्वारा किसान भाइयों से बार बार अपील की जा रही है कि वे अपनी फसल की मंडी में अच्छी तरह सुखाकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों (जैसे कि नमी 17 प्रतिशत) की सीमा अनुसार लेकर आएं। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा धान की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किये हुए हैं और धान के उठान कार्य में भी तेजी लाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा खरीद किये गए धान के भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की अदायगी किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर स्थानांतरित की जाती है। भारत सरकार द्वारा धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 प्रति क्विंटल में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य की मण्डियों और खरीद केंद्रों में किसानों द्वारा लाये गए धान की साफ़ - सफाई का कार्य आढ़तियों द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मंडियों और खरीद केंद्रों पर होने वाले मण्डी श्रम कार्य (जैसे कि भराई, तुलाई, सिलाई, लदाई इत्यादि) के शुल्क दरों की अदायगी भी सरकार द्वारा वहन की जाती है।

नगर परिषद, जींद के दो अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर दंड व मुआवजा भुगतान के निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक प्रकरण में नगर परिषद, जींद के अधिकारियों द्वारा नागरिक सेवा में लापरवाही बरतने और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पाया कि संबंधित अधिकारियों ने 04 जुलाई 2023 को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया था कि अनाधिकृत कॉलोनियों में भी प्रॉपर्टी आईडी में आवश्यक सुधार किया जा सकता है, परंतु उस पर 'अनऑथराइज्ड' टैग बना रहना चाहिए। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पाया कि नगर परिषद, जींद की क्लर्क और सचिव ने उक्त दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे आवेदक को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। आयोग ने टिप्पणी की कि एक सामान्य नागरिक, जो राज्य से बाहर कार्यरत है, को केवल इस कारण नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि अधिकारियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए आयोग ने अधिनियम की धारा 17(1)(ह) के अंतर्गत दोनों अधिकारियों को दोषी ठहराया है। आयोग ने प्रत्येक पर एक हजार रुपये का प्रतीकात्मक दंड लगाया है और साथ ही शिकायतकर्ता को 2500-2500 रुपये कुल 5 हजार रुपये का मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को निर्देशित किया है कि अक्टूबर 2025 के वेतन से 3500-3500 रुपये की कटौती कर नवम्बर 2025 में भुगतान किया जाए और इसकी रिपोर्ट 10 नवम्बर 2025 तक आयोग को भेजी जाए। दंड की राशि को राज्य कोष में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। आयोग ने साथ ही यह भी पाया कि प्रथम अपील (एफजीआरए) के निस्तारण में भी त्रुटि रही है, क्योंकि अपील संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुँची। इस संबंध में जीएम (आईटी), शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सेवाएं और अपीलें सही अधिकारियों (डीओ, एफजीआरए, एसजीआरए) से उचित रूप से मैप हों। अंत में, आयोग ने एसजीआरए-कम-डीएमसी, जींद को भी चेताया है कि उन्होंने न तो 04.07.2023 के निर्देशों का पालन किया और न ही आवेदक को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया। हालांकि, उनकी बिना शर्त माफी और यह प्रथम त्रुटि होने के कारण आयोग ने भविष्य के लिए उन्हें चेतावनी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

जापान दौरे पर हरियाणा प्रतिनिधिमंडल ने टीडीके कॉर्पोरेशन के साथ की अहम बैठक, निवेश को लेकर हुई चर्चा

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठकें कर हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने आज टोक्यो में जापान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टीडीके कॉर्पोरेशन के साथ अहम बैठक कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सेंसर और चुंबकीय सामग्री के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि टीडीके कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी द्वारा ईएमसी सोहना, हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना हरियाणा को ऊर्जा भंडारण तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी और राज्य में रोजगार, नवाचार तथा तकनीकी विकास को गति प्रदान करेगी। बैठक में टीडीके कंपनी के अन्य पार्टनर्स को हरियाणा में एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए निवेश करने हेतु भी प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने टीडीके कॉर्पोरेशन को हरियाणा सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। इसके तहत उद्योगों को सभी प्रकार के एनओसी एवं अनुमोदन सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम शहर में 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित हैं। इतना ही नहीं, लागत को कम करने, बिक्री बढ़ाने और सप्लाई चैन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एन.सी.आर. क्षेत्र में हरियाणा सबसे उपयुक्त डेस्टीनेशन है। क्योंकि, दिल्ली के तीन ओर हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कारोबार के लिए जरूरी सभी सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। उन्होंने आश्वसन दिया कि राज्य सरकार उद्योगों को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री यश गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

टीडीके कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी एटीएल बैटरी हरियाणा में स्थापित कर रही भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापानी कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए किया आमंत्रित

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हरियाणा सरकार निवेशकों को सिंगल-विंडो सिस्टम से दे रही सभी जरूरी एनओसी

नए आपराधिक कानूनों में प्रदर्शनी ने लोगों की जगाई रुचि - डॉ. सुमिता मिश्रा

चंडीगढ़। हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि भारत के नए आपराधिक कानूनों पर कुरुक्षेत्र में लगाई गई ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता, विशेषकर छात्र और युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में इस प्रदर्शनी को उदघाटन किया गया था। यह प्रदर्शनी 11 अक्टूबर तक चलेगी। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के छात्र, पंचायत सदस्य और महिला प्रतिनिधि शामिल हैं। यह प्रदर्शनी यह देखने का अवसर प्रदान करती है कि किस प्रकार सुधारित आपराधिक कानून भारत में पुलिसिंग, जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं को नया रूप दे रहे हैं। प्रदर्शनी में सात प्रमुख विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 स्टॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक स्टॉल आपराधिक न्याय प्रणाली के संचालन का एक इंटरैक्टिव दृश्य प्रस्तुत करता है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि डायल 112 नियंत्रण कक्ष की एक प्रतिकृति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे संकटकालीन मोबाइल कॉलों को शीघ्रता से प्राप्त और संसाधित किया जाता है। आपातकालीन वाहन प्रतिक्रिया (ईवीआर) इकाइयाँ मिनटों में पहुँच जाती हैं, जबकि वैज्ञानिक और फोरेंसिक (एसएफएल) टीमों द्वारा किए गए इंटरैक्टिव प्रदर्शन तकनीक-आधारित साक्ष्य संग्रह की सटीकता और पारदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं। विस्तृत प्रदर्शनियाँ अस्पतालों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और पुलिस विभागों की प्रणालीगत भूमिकाओं को दर्शाती हैं, साथ ही पुरानी और नई प्रक्रियात्मक प्रणालियों के बीच स्पष्ट तुलना भी करती हैं, जो आगंतुकों को पुनर्रचित न्यायालयों और जेल प्रणालियों में न्यायिक सुधारों की परिवर्तनकारी यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आगंतुकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर रहे हैं तथा उन्हें जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना और कानूनी ढांचे में जनता का विश्वास मजबूत करना है। डॉ. मिश्रा ने कहा, 'इन कानूनों की सफलता न केवल पुलिस द्वारा उनके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, बल्कि नागरिकों की जागरूकता और सहयोग पर भी निर्भर करती है।' उन्होंने कहा, 'यह प्रदर्शनी लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करके इस अंतर को पाटने में मदद कर रही है।'

'वोट चोरी' साजिश के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का जनहस्ताक्षर अभियान, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर चुनावी हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाते हुए राजधानी में व्यापक जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सोमवार को बाबरपुर में आयोजित हस्ताक्षर अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और भाजपा पर सुनियोजित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जनता से इस कुतंत्र के खिलाफ हस्ताक्षर लेने की अपील की. बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देवेन्द्र यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाजारों, सड़कों और चौपालों पर उतरे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने «वोट चोर गद्दी छोड़ो» के नारे लगाकर माहौल को राजनीतिक रूप से गरमा दिया. देवेन्द्र यादव ने बताया कि दिल्लीभर में चल रहे हस्ताक्षर अभियान को जनता से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. 1 से 4 अक्टूबर तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठकों में भी इस विषय पर गहन चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अग्रिम संगठन- युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल और एनएसयूआई भी अपने स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जैन ने की. इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा, हाजी भूरे खान, हाजी जरीफ, डा. पी.के. मिश्रा, मनोज यादव समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने भाजपा पर वोट चोरी के सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की. देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश के संवैधानिक अधिकार- वोट देने के अधिकार, पर प्रहार किया है. उन्होंने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि, दो विधानसभाओं के उदाहरण से ही यह साबित हो गया है कि भाजपा वोट चोरी की साजिश में लिप्त रही है. यादव ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर देशभर में यह जनहस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. «देश के युवा, छात्र, जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे» को दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिशों को अब देश का युवा समझ चुका है और सबूतों के साथ कांग्रेस इस लड़ाई को सड़कों से संसद तक ले जाएगी. देवेन्द्र यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार का पहला कर्तव्य जनता के अधिकारों और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना होता है, लेकिन भाजपा ने ईमानदार चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वोट चोरी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से सत्ता हासिल की. उन्होंने कहा कि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सार्वजनिक रूप से वोट चोरी की बात स्वीकार की है. वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश का युवा अब समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है.

आर्थराइटिस, डायबिटीज का इलाज खोजने वाले वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल

नई दिल्ली । शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना आवश्यक है अन्यथा यह हमारे अपने अंगों पर ही हमला कर सकती है। मैरी ई. ब्रनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन साकागुची को इस संबंध में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को बेहतर समझने की खोज- पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है।

इन खोजों ने अनुसंधान की नई राह खोल दी है। इससे कैंसर तथा ऑटोइम्यून रोगों के उपचारों को और प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। पिछले साल का पुरस्कार अमेरिकी नागरिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को सूक्ष्म 'आरएनए' (राइबोन्यूक्लिक एसिड) की खोज के लिए दिया गया था।

यह सम्मान 1901 से 2024 के बीच 115 बार 229 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किया जा चुका है। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अनियंत्रित होने और शरीर के ही ऊतकों पर हमला करने से रोकता है।

*मैरी ई. ब्रनको (जन्म 1961) ने अमेरिका के प्रिंस्टन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

*फ्रेड रैमस्डेल (जन्म 1960) ने 1987 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को स्थित सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स में वैज्ञानिक सलाहकार हैं।

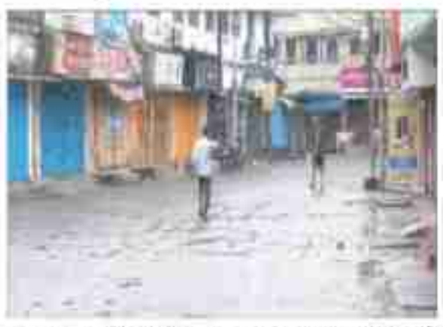

कटक में हिंसा के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू लागू, 60 पुलिस पलटन तैनात; प्रशासन ने जनता से की अपील

कटक । ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा के पंडालों की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद प्रशासन ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू 6 अक्तूबर रात 10 बजे से 7 अक्तूबर सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा। ये कर्फ्यू भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने बताया कि इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा, जरूरी सेवाएं जैसे दवाखाने, किराना दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर और कदम उठाए जाएंगे। कर्फ्यू से प्रभावित मुख्य इलाकों में दरगाह बाजार, मंगलाबाग, पुरिघट, लाल बाग और जगतपुर शामिल हैं। कटक में शांति बनाए रखने के लिए 60 पुलिस पलटन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), बीएसएफ, सीआरपीएफ और ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स के आठ कंपनियां महत्वपूर्ण जगहों और चौराहों पर तैनात की गई हैं।

आम जनता से डीजीपी की अपील

वहीं ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी जानकारी के लिए पुलिस की वेबसाइट, कमिश्नरेट की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल देखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कटक में स्थिति अब नियंत्रण में है और हिंसा में शामिल सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सत्ता पक्ष और विपक्ष ने की शांति की अपील

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्थानीय विधायक नागरिकों से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माझी ने कहा, साम्प्रदायिक सौहार्द पर कोई समझौता नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, नहीं दी तत्काल राहत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट 6 अक्तूबर को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में तत्काल कोई फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ के अब मामले में आगे 14 अक्तूबर को सुनवाई करेगी। गीतांजलि की तरफ से इस मामले में वकील कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने जजों से कहा कि परिवार को सोनम को हिरासत में रखे जाने की वजह नहीं बताई गई है।

उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से दलील देते हुए कहा कि हिरासत में रखे गए व्यक्ति (सोनम वांगचुक) को हिरासत की वजहें बताई गई हैं और उनकी पत्नी को इससे जुड़ी प्रति देने पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में हुए प्रदर्शन के दो दिन बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर किया गया था, जिसमें चार लोगों की मौत और करीब 90 लोग घायल हुए थे।

केजरीवाल का बिहार दांव : आप ने जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली सूची, अकेले लड़ेगी चुनाव!

नई दिल्ली । अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बिहार में नई पार्टी आप ने जुलाई में घोषणा की थी कि वह बिहार चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भारत ब्लॉक का हिस्सा थी, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी। बाद में, आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पुष्टि की कि पार्टी बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी। आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख भारद्वाज ने इस साल की शुरुआत में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, हम बिहार चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं।

जयपुर अग्निकांड : प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा- मिले उचित मुआवजा, हो त्वरित जांच

जयपुर ।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने और घटना की गहन जांच कराने की अपील की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जयपुर के एक सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से कई मरीजों की दर्दनाक मौत की खबर बेहद हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। कांग्रेस नेता ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पोस्ट में लिखा था, मैं राज्य सरकार से

प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने, इस घटना की त्वरित जांच करने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई करने की अपील करता हूं। रविवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लग गई। जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस दुखद हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की। पुलिस आयुक्त ने एएनआई को बताया कि प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी; इस बीच, फॉरेंसिक टीम कारण का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की लापरवाही की आलोचना करते हुए उस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। डोटासरा ने एएनआई को बताया कि सिस्टम की लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली है... राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है... लोग कफ सिरप पीकर मर रहे हैं और

जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग, 8 मरीजों की मौत

स्वास्थ्य मंत्री के सामने नारेबाजी, हंगामा; पुलिस से भिड़े आरएलपी कार्यकर्ता

स्वास्थ्य मंत्री दवा कंपनियों को क्लीन चिट दे रहे हैं... राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है...। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गोपाल शर्मा ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। भाजपा विधायक ने एएनआई से कहा, यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन लोगों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

पटना मेट्रो शुरू, नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन

पटना।

पटनावासियों का लंबा इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (6 अक्टूबर) पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के 3.6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से के पहले चरण का उद्घाटन किया। 7 अक्टूबर से मेट्रो आम जनता के लिए चलेगी। पटना मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन समेत छह भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का भी शिलान्यास किया। मेट्रो का प्रारंभिक चरण फिलहाल केवल लगभग 3.6 किलोमीटर की दूरी तक ही चलेगा, जो शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तीन डिब्बों वाली पटना मेट्रो ट्रेन में लगभग 138 यात्री बैठ सकते हैं, जबकि प्रति ट्रिप 945 अतिरिक्त यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। पटना मेट्रो के उद्घाटन से शहर के परिवहन नेटवर्क में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा, यातायात की भीड़ कम होगी और पटना में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पटना मेट्रो का किराया 15 रुपये से 30 रुपये के बीच तय किया गया है। आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये होगा, जबकि न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक का किराया 30 रुपये होगा। मेट्रो प्रतिदिन चलेगी, फिलहाल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, हर 20 मिनट में ट्रेनें चलेंगी। प्रत्येक ट्रेन में महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए 12 आरक्षित सीटें भी होंगी। पटना मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया है। प्रत्येक कोच में 360-डिग्री सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन बटन और माइक्रोफ़ोन लगे हैं, जिनसे यात्री सीधे मेट्रो चालक से संवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कोचों में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, आगे की ओर आपातकालीन द्वार और बेहतर सुरक्षा के लिए दो हिस्सों में बंटे स्लाइडिंग दरवाज़े भी हैं। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए, कोचों को मधुबनी पेंटिंग और गोलघर, महावीर मंदिर और बुद्ध जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के भगवा रंग में चित्रित रूपांकनों से सजाया गया है।

शिवसेना यूबीटी-मनसे का गठबंधन दिल और दिमाग से-संजय राउत

मुंबई । शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की रविवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर सोमवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी बातचीत राजनीतिक थी और निकाय चुनावों से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन दिल और दिमाग से होगा। मीडिया से बात करते हुए, संजय राउत ने कहा कि ठाकरे भाइयों के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध मजबूत हो गए हैं, और भले ही कोई उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश करे, लेकिन अब बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन दिल और दिमाग से बनेगा। यह कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है।

यह तन-मन-धन से बना गठबंधन है। मुंबई का मेयर असली भगवा रंग वाला एक मराठी होगा।

वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर 500 सफाई कर्मियों स्वच्छता मित्रों का योगी ने किया सम्मान

वाराणसी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी में लगभग 500 सफाई कर्मियों स्वच्छता मित्रों का भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को अंगवस्त्रम, सेफ्टी कोट और मिष्ठान आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित सफाई कर्मियों के चेहरे पर संतोष और आत्मसम्मान का भाव स्पष्ट रूप से देखा गया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद परोसकर उन्हें पवित्र किया, जिससे वे काफी गदगद दिखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन कबीरचौरा पिपलानी कटरा के पास स्थित सरोजा पैलेस में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी के 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के समापन अवसर पर «स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह» का आयोजन किया। इस समारोह में उन्होंने सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि की जयंती, जो 7 अक्टूबर को है, को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सफाई कर्मियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें प्रतिमाह 16 से 20 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे। इससे सफाई कर्मियों का शोषण नहीं हो

सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मियों की चिंता उनकी सरकार कर रही है। सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपये निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके परिवार का हर वर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कल शरद पूर्णिमा है और भगवान वाल्मीकि की जयंती है। उन्होंने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि इन अवसरों पर पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी द्वारा आयोजित 75 दिवसीय कार्यक्रम अद्भुत रहा। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिससे 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा और कहा कि स्वच्छता से बीमारियों का निवारण होता है।

उन्होंने वार्ड भ्रमण के दौरान 33,000 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और समाधान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय बताया। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहने और आम जनमानस से संवाद करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी अश्विनी त्यागी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महापौर अशोक तिवारी, और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

6 और 11 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 14 नवंबर को

बिहार में बजा चुनावी बिगुल

- बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव
- कुल 40 दिन की चुनाव प्रक्रिया
- बिहार में 7.2 करोड़ वोटर
- 14 लाख मतदाता पहली बार करेंगे वोट

नई दिल्ली ।

बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। बिहार में कुल दो चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण का वोट 6 नवंबर को डाले जाएंगे जबकि दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होंगे। चुनावी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में मुख्य मुकाबला भाजपा-जदयू की गठबंधन वाले एनडीए और राजद-कांग्रेस के गठबंधन वाले महागठबंधन के बीच है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में

***बिहार में चुनावी मशीनरी, चुनाव के लिए 90712 बीएलओ**

***वोटर्स की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल- चुनाव आयोग**

7.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से चार लाख वरिष्ठ नागरिक हैं और 14,000 मतदाता 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। चौदह लाख मतदाता पहली बार मतदान कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी

***अफवाह फैलाने वालों पर होगा एक्शन- सीईसी**

***हर बूथ पर लगभग 818 वोटर- ज्ञानेश कुमार**

***सभी दलों को दी गई अंतिम मतदाता सूची- सीईसी**

राजनीतिक दलों को दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं को बताना चाहता है कि हम कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को पूरी तरह निष्पक्षता से काम करने और हितधारकों के लिए सुलभ रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी मीडिया हाउस या व्यक्ति के माध्यम से कोई गलत सूचना मिलती है, तो चुनाव आयोग उसका खंडन करेगा।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर CAPF को पहले से तैनात किया जाएगा...सभी अधिकारियों को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा।

अगर किसी भी माध्यम या प्लेटफ़ॉर्म पर कोई फ़र्ज़ी खबर या गलत सूचना है, तो उसका खंडन किया जाएगा। ड्रग्स, शराब और नकदी के लेन-देन को रोकने के लिए सभी चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वर्तमान में देखें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं। एनडीए में भाजपा के पास 80, जदयू के पास 45 और जीतन राम मांझी की हम (एस) के पास 4 सीटें हैं। इसके अलावा, एनडीए को दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर, महागठबंधन में राजद को 77, कांग्रेस को 19, भाकपा (माले) को 11, माकपा को 2 और भाकपा की 2 सीटें शामिल हैं।